आकाशवाणी
क्षेत्रीय समाचार
देहरादून (उत्तराखण्ड)
शुक्रवार 10.01.2025
समय 07.20

मुख्य समाचार :–

- गृह मंत्री अमित शाह ने कहा– सरकार पुलिस बलों को स्मार्ट बलों में बदलने के लिये प्रतिबद्ध।
- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऊधमसिंह नगर के चकरपुर में सोलह करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बने वन चेतना केंद्र स्पोर्ट्स स्टेडियम का लोकार्पण किया।
- देहरादून में 12 जनवरी को आयोजित होने जा रहे अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी सम्मेलन की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
- गणतंत्र दिवस परेड देखने के लिये लगभग दस हजार विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया है।

लोकार्पण

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऊधमसिंह नगर जिले की खटीमा तहसील के चकरपुर में सोलह करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बने वन चेतना केंद्र स्पोर्ट्स स्टेडियम का लोकार्पण किया। आगामी राष्ट्रीय खेलों की मलखंभ प्रतियोगिता यहीं आयोजित होगी। स्टेडियम को युवाओं के लिए खेल प्रतिभा को निखारने का मंच बताते हुए श्री धामी ने बताया कि यह स्टेडियम आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। नवनिर्मित स्टेडियम में बास्केटबॉल, फुटबॉल, वालीबॉल, कबड्डी जैसे खेलों के मैदानों का निर्माण कराया गया है। साथ ही खिलाड़ियों के ठहरने के लिए हॉस्टल और इनडोर कार्यक्रमों के लिए बहुउद्देश्यीय हॉल भी बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल युवाओं के मानसिक और शारीरिक विकास के साथ अनुशासन, टीमवर्क और संघर्षशीलता के गुण विकसित करते हैं। राज्य सरकार खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नई खेल नीति के तहत पदक विजेताओं को सरकारी नौकरियां, मुफ्त प्रशिक्षण और खेल छात्रवृत्ति जैसी सुविधाएँ दे रही है। उन्होंने जोर देते हुये कहा कि सरकार खटीमा क्षेत्र के विकास के लिये हर संभव प्रयास करेगी।

प्रतिबद्धता

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ–साथ आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों का सामना करने के लिए भारतीय पुलिस बलों को स्मार्ट बलों में बदलने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में कल पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो में एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने यह बात कही।

बैठक के दौरान, श्री शाह ने ब्यूरो के 6 प्रभागों की उपलब्धियों, चल रहे कार्यों और भविष्य की रूपरेखा की भी समीक्षा की। उन्होंने नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन की दिशा में पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो द्वारा किए गए प्रयासों और पहलों की भी समीक्षा की।
उन्होंने कहा कि पुलिस ब्यूरो को जमीनी स्तर पर कानून व्यवस्था में आने वाली चुनौतियों की पहचान कर उन पर अनुसंधान करना चाहिए और उनके समाधान खोजने की दिशा में काम करना चाहिए।

आधार केंद्र सक्रियता

देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने जिले में बंद पड़े 10 आधार केंद्रों को सक्रिय करने के लिए दक्ष ऑपरेटरों की नियुक्ति की स्वीकृति दी है। ये केंद्र तहसील, ब्लॉक और नगर पंचायत स्तर पर संचालित किए जाएंगे, जिससे आधार अपडेट संबंधित समस्याओं का समाधान होगा।

अनाधिकृत निर्माण जांच

देहरादून एयरपोर्ट के पास अनाधिकृत निर्माण कार्यों की ख़बर के बीच ज़िलाधिकारी सविन बंसल ने इसकी जांच के निर्देश दिये हैं। उन्होंने एयरपोर्ट के समीप बिना एनओसी के हो रहे अनाधिकृत निर्माण पर डोईवाला के उपजिलाधिकारी, एमडीडीए और एयरपोर्ट के अधिकारियों को संयुक्त निरीक्षण कर आख्या प्रस्तुत करने को कहा है। ऋषिपर्णा सभागार में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण देहरादून पर्यावरण समिति की बैठक में उन्होंने एयरपोर्ट के 10 किलोमीटर परिधि में पक्षियों से सुरक्षा के लिए प्रभावी उपाय करने और क्षेत्र में एकत्रित कूड़े का निस्तारण कर गार्बेज प्वाइंट हटाने के आदेश भी जारी किए।

हाईकोर्ट

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बागेश्वर जिले की कांडा तहसील के कई गांवों में खड़िया खनन से आई दरारों के मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए सख्त रुख अपनाया है। मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने उपस्थित अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने खान अधिकारी का तत्काल तबादला करने का निर्देश दिया और पुलिस अधीक्षक को आदेश दिया कि वे कल तक खनन में लगी सभी मशीनों को सीज कर अपनी रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करें।

अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी सम्मेलन तैयारियाँ

देहरादून में 12 जनवरी को आयोजित होने जा रहे अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी सम्मेलन की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसी क्रम में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय में विभिन्न विभागों के साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उद्योग, पर्यटन, कौशल विकास, कृषि और उद्यान विभागों ने सम्मेलन में आयोजित होने वाले सत्रों की रूपरेखा प्रस्तुत की।

मुख्य सचिव ने सम्मेलन के दौरान राज्य की लोक संस्कृति, खानपान, स्थानीय हस्तशिल्प और उत्पादों के बेहतरीन प्रदर्शन के निर्देश दिए। गौरतलब है कि इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिये अब तक 17 देशों से 60 प्रवासियों ने पंजीकरण कराया है, जिनमें यूएई, जापान और न्यूजीलैंड जैसे देशों के प्रतिनिधि शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन को राज्य के विकास में प्रवासियों की भूमिका को सुनिश्चित करने के लिये महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सम्मेलन में निवेश, पर्यटन, कौशल विकास, उच्च शिक्षा, हर्बल मेडिसिन और कृषि क्षेत्र से संबंधित चर्चाएँ की जाएंगी।

हेल्पलाइन सेवा

आगामी 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए चार अंकों का टोल फ्री नंबर जल्द उपलब्ध हो सकता है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि राष्ट्रीय खेल सचिवालय ने संचार मंत्रालय को पत्र भेजकर 10 जनवरी से 28 फरवरी 2025 तक यह सुविधा प्रदान करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि हेल्पलाइन सेवा इवेंट शेड्यूल, आपातकालीन सेवाओं और अन्य आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए सहायक होगी।

परीक्षा पे चर्चा

परीक्षा पे चर्चा के आठवें संस्करण के लिए देश–विदेश से छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से दो करोड़ 70 लाख से अधिक पंजीकरण प्राप्त हुए हैं। इस कार्यक्रम के लिए माई जीओवी डॉट इन पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण 14 दिसम्बर को शुरू हुआ था और इस महीने की 14 तारीख तक इसके लिए आवेदन किया जा सकेगा। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा पे चर्चा पहल, परीक्षा से जुड़े तनाव को कम करने और परीक्षा को एक उत्सव में बदलने के लिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन के रूप में आगे बढ़ रही है। कार्यक्रम मानसिक स्वास्थ्य पर बातचीत और परीक्षाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए छात्रों के बीच लोकप्रिय है।

आमंत्रण

गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर इस वर्ष लगभग दस हज़ार विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। इनमें सरपंच, आपदा राहत कार्यकर्ता, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जल योद्धा, हथकरघा और हस्तशिल्प कारीगर के साथ ही मन की बात के प्रतिभागी, माई भारत स्वयं सेवक, पूर्वोत्तर राज्यों के अतिथि और सर्वश्रेष्ठ स्टार्ट–अप शामिल हैं। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि आमंत्रित अतिथियों में से कुछ स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से रोजगार सृजन सुनिश्चित करने के लिए अनुकरणीय कार्य कर रहे हैं।

पीपीओ फॉर्म

अब राज्य आन्दोलनकारियों को भी स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी पेंशनरों की तर्ज पर कोषागार के माध्यम से पेंशन का भुगतान किया जाएगा। अपर जिलाधिकारी पीआर चौहान ने बताया कि इसके लिए राज्य आंदोलनकारियों को पेंशन पेमेंट आर्डर– पीपीओ के निर्धारित प्रारूप पर नाम, पति या पिता का नाम, स्थायी निवास का पता, संयुक्त फोटो, पेंशन प्रारंभ होने का वर्ष व दिनांक सहित अन्य जानकारी कोषागार को उपलब्ध कराये जाने है। उन्होंने बताया कि राज्य आन्दोलनकारी पेंशन प्राप्त कर रहे चिन्हित राज्य आन्दोलनकारी निर्धारित पेंशन प्रारूप सम्बन्धित उपजिलाधिकारी के माध्यम से उपलब्ध करायेगें। राज्य आन्दोलनकारी, नियमित पेंशन भुगतान का प्रारूप नैनीताल डॉट एनआईसी डॉट इन और अपने क्षेत्र के उपजिलाधिकारी या तहसील कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं।

एक नज़र आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर––

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 28 जनवरी को उत्तराखंड आएंगे। इस ख़बर पर अमर उजाला ने लिखा है– बदरीनाथ–केदारनाथ की समीक्षा करेंगे पीएम। समाचार पत्र के अनुसार शीतकालीन यात्रा का संदेश देने के लिये प्रधानमंत्री गंगोत्री के शीतकालीन प्रवास स्थल मुखबा या यमुनोत्री के खरसाली जा सकते हैं।

बागेश्वर के जिला खान अधिकारी को हटाने के आदेश। इस शीर्षक के साथ हिंदुस्तान समाचार पत्र की ख़बर है– खड़िया खनन का हाइकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान। 24 घंटे में एसपी को खडिया खनन में लगी मशीनों को सीज कर रिपोर्ट पेश करने के आदेश।

निकाय चुनाव पर दैनिक जागरण लिखता है– प्रदेश में 563 संवेदनशील तो 426 अति संवेदनशील बूथ। समाचार पत्र के अनुसार वर्ष 2018 के निकाय चुनाव के मुकाबले इस बार संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों का आंकड़ा कम हुआ है।

राष्ट्रीय खेलों के लिये टोल फ्री नंबर की सुविधा जल्द। इस ख़बर को पहले पृष्ठ पर स्थान देते हुये राष्ट्रीय सहारा समाचार पत्र लिखता है– राष्ट्रीय खेल सचिवालय ने संचार मंत्रालय से आज से 28 फरवरी 2025 तक यह सुविधा उपलब्ध कराने की अपेक्षा की है।

दून से प्रयागराज के लिये चलेगी कुंभ स्पेशल। इस शीर्षक के साथ नवोदय टाइम्स की ख़बर है– 18 जनवरी से 28 फरवरी तक कुछ छह बार यह रेलगाड़ी चलेगी।